जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)

पहल नई योजनाएं लागू कर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का रहा साल 2015

7420 अभ्यर्थियों को दी विभिन्न पदों पर नियुक्ति

वित्तीय घाटे में 4200 करोड़ रुपए की कमी

जयपुर, 13 जनवरी। प्रदेश की विद्युत निगमों द्वारा वर्ष 2015 में उपभोक्ताओं को कम लागत पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने एवं वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। लागू की गई योजनाओं की खास बात यह है कि इन योजनाओं का सकारात्मक परिणाम भी बीते साल में ही मिलना शुरु हो गया हैं। बिजली के उत्पादन, प्रसारण, वितरण के साथ ही अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से वर्ष 2015 की पहली छमाही में वित्तीय घाटे में 4200 करोड़ रुपए की कमी करने के साथ ही गत वर्ष पांचो विद्युत निगमों में 7420 चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति भी दी गई है।

विद्युत वितरण

ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने बताया कि आमजन से सीधा जुड़ा होने के कारण विद्युत वितरण क्षेत्र में वर्ष 2015 में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई, जिससे शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के साथ ही उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान के प्रयास भी किए गए। विद्युत वितरण में लागू की गई नई योजनाओं के तहत **हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार** अभियान के अन्तर्गत 30 अगस्त से 11 अक्टूबर, 2015 के मध्य 4 कैम्प आयोजित कर 2 लाख 84 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए, जिसमें से 1 लाख से अधिक कनेक्शन तो 4–6 घण्टे में शिविर स्थल पर ही जारी कर दिए गए। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरिक समाधान के लिए तीनों डिस्कॉम में सातों दिन चौबीसों घण्टे कार्यरत एक–एक **केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर** की स्थापना कर बिजली की 6 तरह की शिकायतों के दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस सुविधा के तहत गत वर्ष करीब 50 हजार शिकायतों का डिस्कॉम के काल सेन्टर्स के माध्यम से समाधान किया गया। बिजली की बचत को बढावा देकर खपत में कमी के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि0 के सहयोग से घरेलू ऊर्जा दक्षता लाईटिंग कार्यक्रम के तहत **एलईडी होम लाईटिंग योजना** के अन्तर्गत 7 वॉट के 60 लाख एलईडी बल्ब बाजार से बहुत कम कीमत पर वितरित किए गए। इससे प्रदेश में लगभग 73 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी।

वर्ष 2015 में ही **फीडर इम्प्रूवमेन्ट** एवं **सब–स्टेशन इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम** भी शुरु किया गया तथा 33 केवी फीडरों पर **ट्रीपिंग** में कमी के लिए सितम्बर, 2015 से अभियान चलाया गया इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए तथा ट्रीपिंग की संख्या प्रतिमाह 12 से घटकर 9 रह गई। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान के तौर पर 50 हजार से अधिक **हाई रिस्क पाइन्टस** को चिन्हित कर उन पर आवश्यक सुधार कार्य किया गया। विद्युत वितरण निगमों में वर्ष 2015 में विभिन्न पदों पर 5345 लोगों को नियुक्तियां दी है।

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए दो **प्रोत्साहन योजनाएं** लागू की गई है पहली योजना में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को निधारित लक्ष्य के अनुरुप कम करने वाले ओएण्डएम सब–डिविजन के कर्मचारियों को अधिकतम एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा दूसरी योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक डिस्कॉम के 10 कर्मचारियों को ऊर्जा दिवस पर ऊर्जा चक्र से सम्मानित किया जाएगा। **सब–डिविजन** 33 केवी के 217 नए सब–डिविजन भी वर्ष 2015 में चालू किए गए। **प्री पेड मीटर** लगाने की शुरुआत करते हुए तीनो डिस्कॉम द्वारा राजकीय कनेक्शनों पर 4869 प्री पेड

मीटर लगाए गए हैं। **समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि** में गत वर्ष के सापेक्ष अप्रेल से नवम्बर, 2015 में 1 प्रतिशत की कमी हुई है तथा बड़े उपभोक्ताओं अतिरिक्त यह कमी 3.45 प्रतिशत रही है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वितरण तंत्र की मजबूती एवं 7 लाख 30 हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 2819 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इसी तरह शहरों में उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदढ करने के लिए **आईपीडीएस** योजना में 1303 करोड़ रुपए स्वीकत किए हैं। वर्ष 2015 में ही राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का गठन किया गया है। यह निगम अगले वित्तीय साल से कार्य करना शुरु कर देगा। बिजली कम्पनियों का घाटा 2015 के पहले 6 महिनों 4200 करोड़ रुपए कम हो गया है।

विद्युत प्रसारण

विद्युत प्रसारण में भी साल 2015 में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। अन्ता एवं फागी में 765 केवी के दो सब–स्टेशन की स्थापना कर राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 765 केवी ग्रिड सब–स्टेशन हैं। 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी के बड़े ग्रिड सब–स्टेशन वर्ष 2015 में 36 बनाए गए हैं जबकि 2014 में केवल 15 ही बनाए गए थे। राजस्थान की प्रसारण कम्पनी कुछ उन राज्यों की प्रसारण कम्पनियों में शामिल हो गई जिसकी लाईने बिजली के अर्न्तराज्यीय प्रसारण में काम में लाई जा रही है। इससे प्रसारण निगम को 93.41 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है। खर्चों में कमी लाने के लिए प्रसारण निगम द्वारा पहली बार अपने 132 केवी के 6 सब–स्टेशनों के रख–रखाव का कार्य आउटसोर्स करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं इससे प्रत्येक सब–स्टेशन के रख–रखाव का 30 लाख रुपए सालाना का खर्चा बचेगा। वर्ष 2015 में 1437 लोगों को नियुक्ति देने के साथ ही संगठन के ढांचे में भी परिवर्तन किया जा रहा है जिसके तहत निगम में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर कर्मचारियों की संख्या को कार्य की आवश्यकता के अनुसार 12946 से कम कर 9924 करने के लिए वित विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

विद्युत उत्पादन

काली सिन्ध थर्मल पावर प्राजेक्ट, झालावाड़ की 600 मेगावाट की इकाई को साल 2015 में शुरु कर विद्युत उत्पान क्षमता में बढोतरी की गई है। साल 2015 में ही कांटे बेसिन एवं पारसा कोल ब्लॉक्स को उत्पादन निगम को आवंटन किया गया एवं कांटे बेसिन एवं पारसा ईस्ट की उत्पादन क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन से 48.5 लाख मीट्रिक टन तक बढाई गई। इसके साथ ही उत्पादन लागत में कमी करने के लिए छबड़ा व काली सिन्ध पावर स्टेशनों को निजि क्षेत्र को देने के लिए केबीनेट नोट तैयार कर लिया गया है। उत्पादन निगम का वित्तीय घाटा साल 2014 2637 करोड़ रुपए था इसके वित्तीय साल 2015–16 में 1400 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उत्पादन निगम में भी गत वर्ष 638 लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी गई है।

अक्षय ऊर्जा

ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोंत के तहत प्रदेश में वर्ष 2015 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 397.75 मेगावाट की वृद्वि की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़कर 1234 मेगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भी 800.80 मेगावाट की बढोतरी से उत्पादन क्षमता 3866.345 मेगावाट हो गई है। राज्य मे 25 हजार मेगावाट क्षमता के सौलर पावर प्रोजेक्ट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से 26 हजार मेगावाट क्षमता के सौलर पार्क्स की स्थापना के लिए अनुबन्ध किये गये है। राज्य में रूफटॉफ सौलर पीवी प्लान्टस को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग रेग्यूलेशन भी जारी कर दिये गये है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 351/2015